P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-8* November-2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

# लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूमिका: एक विश्लेषण

# Prime Minister Narendra Modi's Role in Democratic Governance: An Analysis

**Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication: 24/11/2021**

**अंकिता त्रिपाठी**
शोधार्थी,
राजनीतिक विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, अध्ययनशला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.), भारत

**सारांश**

भारतीय लोकतंत्र में सबसे मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री की होती है, जो देश का मुखिया होता है। जो पूरे देश का नेतृत्व करता है। विदेशो से सम्बन्ध बनाये रखने में मुख्य भूमिका निभाता है, इसके साथ ही साथ अनेक क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ाने में नई-नई योजनाओं और नितियों का संचालन करता है। किसी भी सरकार में बिना प्रधानमंत्री के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यदि देश में आपातकाल की स्थिति आती है, तो राजनीतिक स्तर पर वह आपदा प्रबंधन का प्रमुख भी होता है। प्रधानमंत्री भारत की तीनों सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख भी होता है। जब देश संकट मे हो या कोई विपदा में तो प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से जनकल्याणकारी फेसले लेने में सक्षम होता है।

The main role in Indian democracy is that of the Prime Minister, who is the head of the country. He is the head of the whole country. Who leads the whole country. Plays a main role in maintaining relations with foreign countries, along with it, conducts new schemes and policies in carrying forward the development work in many areas. No work can be completed in any government without the Prime Minister. If there is a state of emergency in the country, then he is also the head of disaster management at the political level. The Prime Minister is also the political head of the three armies of India. When the country is in crisis or in some calamity, the Prime Minister is able to take public welfare decisions of his own free will.

**मुख्य शब्द:** लोकतान्त्रिक, प्रधानमंत्री, शसन प्रणाली,नीतियाँ, योजनाएँ ।
**Keywords:** Democratic, Prime Minister, Governance System, Policies, Schemes.

**प्रस्तावना**

**2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव**

गुजरात में सफलतापूर्वक 3 बार चुनाव जीतने के बाद अब नरेन्द्र मोदी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। 2013 के सितम्बर माह में नरेन्द्र मोदी को 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया।1 जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्री लालकृष्ण आडवानी जी भी इन विरोधियों में शामिल थे। नरेन्द्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में एक मुख्य भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले कई लोगों ने कहा कि यदि नरेन्द्र मोदी उम्मीदवार नहीं होते तो शायद वह किसी और पार्टी को वोट देते। चुनाव को नरेंद्र मोदी पर जनमत संग्रह के रूप में वर्णित किया गया था।2

अभियान के दौरान, मोदी ने पिछली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के तहत भ्रष्टाचार के घोटालों पर ध्यान केंद्रित किया। नरेन्द्र मोदी की एक राजनेता के रूप में उनकी छवि पर काम किया, जिन्होंने गुजरात में सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि की थी। मोदी ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया, जो किसी भी विशिष्ट नीतियों पर ध्यान केंद्रित किए बिना विकास ला सके। उनके संदेश को युवा भारतीयों और मध्यम वर्ग के नागरिकों के बीच समर्थन मिला। मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता के लिए मोदी की प्रतिबद्धता के बारे में चिंताओं को कम करने में सक्षम थी, जिन क्षेत्रों में उन्हें पहले आलोचना मिली थी। चुनाव के पूर्व मीडिया द्वारा 2002 के गुजरात दंगों के कारण नरेन्द्र मोदी को घेरने की कोशिश की गयी।3 परन्तु अभियान के दौरान भाजपा ने नागरिकों की सोच को तो बदला ही साथ ही नरेन्द्र मोदी के विकास के गुजरात मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रही। हालांकि, हिंदुत्व अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के अभियान को मीडिया में इसके व्यापक प्रभाव द्वारा सहायता मिली। मोदी के अभियान ब्लिट्ज की लागत लगभग 50 बिलियन ( $700 मिलियन) थी और कॉर्पोरेट दाताओं से व्यापक वित्तीय सहायता प्राप्त की। अधिक पारंपरिक अभियान विधियों के अलावा, मोदी ने सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया और होलोग्राम के माध्यम से 1000 से अधिक रैलियों को संबोधित किया।

चुनाव परिणामों में भाजपा ने 31./.वोट हासिल किए तथा लोकसभा में 282 से अधिक सीटें प्राप्त की थीं।41984 के बाद से अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई। कांग्रेस के साथ-साथ उत्तर भारत में क्षेत्रीय दलों के साथ मतदाताओं का असंतोष भाजपा की सफलता का

एक और कारण था। चुनावों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी भरपूर समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों मे जहाँ भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने उच्च-जाति के हिंदुओं से असाधारण रूप से उच्च समर्थन प्राप्त किया। 10 प्रतिशत मुस्लिम वोट जीते जोकि पहले भी जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने देश के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।
भारतीय जनता पार्टी की जीत की भयावहता ने कई टिप्पणी कारों को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि चुनाव ने प्रगतिशील दलों से दूर और दक्षिणपंथ की ओर एक राजनीतिक अहसास का गठन किया। अपनी जीत की घोषणा करने वाले मोदी के ट्वीट को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राज्य से पूंजीवाद और हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से दूर एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में बताया गया।

मोदी 2014 के आम चुनाव में स्वयं दो निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए उम्मीदवार थे। एक जगह उत्तर प्रदेश की वाराणसी थी और दूसरी उनके गृह राज्य गुजरात की वडोदरा।5 अपने चुने हुए दोनों निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने विजय हासिल की। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के नेता एवं संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और वडोदरा में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को हराया। नरेंद्र मोदी जी सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के संसद दल के नेता चुने गए। तथा उन्हें भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गयी। संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो एक सांसद एक ही लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तथा दोनों स्थानों पर भारी मत से जीतने वाले नरेन्द्र मोदी ने अपने गृहराज्य की वड़ोदरा की सीट त्याग दी तथा वाराणसी से सांसद बने रहे।

**प्रधानमन्त्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का शासन**

26 मई 2014 वह दिन था जब नरेन्द्र दामोदरदास मोदी में प्रधानमन्त्री पद की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और उन्हें अपने दल का नेता चुना। इस दिन से पहले जितने भी प्रधानमन्त्री बने वह स्वतंत्रता के पहले पैदा हुए थे परन्तु नरेन्द्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमन्त्री बने जो भारत की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए। मोदी के प्रधानमन्त्री बनते ही शक्तियों का केन्द्रीयकरण प्रारम्भ हुआ। मोदी के प्रधानमन्त्री बनते ही कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। शुरुआत में राज्यसभा या भारतीय संसद के ऊपरी सदन में बहुमत की कमी के कारण मोदी ने कई अध्यादेश पारित किए। दिसंबर 2014 में मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग के साथ योजना आयोग को समाप्त कर दिया।6 इस कदम के साथ प्रधानमन्त्री ने सत्ता के केन्द्रीयकरण पर और बल दिया। योजना आयोग को सरकार में अक्षमता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका नहीं निभाने के लिए पिछले वर्षों में भारी आलोचना मिली थी। हालाँकि, 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से, यह संबंधित उपायों के लिए जिम्मेदार प्रमुख सरकारी निकाय था।

मोदी सरकार ने प्रशासन के पहले वर्ष में कई नागरिक समाज संगठनों और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ खुफिया ब्यूरो द्वारा जांच शुरू की।7 उन्होंने जाँच इस आधार पर कराई और पाया कि ये संगठन आर्थिक विकास को धीमा कर रहे थे। उनकी बहुत आलोचना की गयी। अंतर्राष्ट्रीय मानव सहायता संगठन मेडेकिंस संस फ्रंटियर उन समूहों में शामिल थे जिन्हें दबाव में रखा गया था। प्रभावित अन्य संगठनों में सिएरा क्लब और अवाज शामिल हैं। सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। इससे मोदी की कार्यशैली को लेकर भाजपा के भीतर असंतोष पैदा हो गया और उन्होंने इंदिरा गाँधी की शासन शैली से तुलना की।

नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमन्त्री बनते ही शुरूआती तीन वर्षों में लगभग 1,200 कानूनों को निरस्त किया। पिछली सरकारों ने 64 वर्षों की लम्बी समयावधि में लगभग 1,301 ऐसे कानून निरस्त किए गए थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को ष्मन की बातष् शीर्षक से एक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया, यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ कि सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति की इंटरनेट पहुँच प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण को बढ़ावा देना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

मोदी ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए "उज्जवला योजना" शुरू की। इस योजना ने 2014 की तुलना में 2019 में एलपीजी की खपत में 56ः की वृद्धि की है। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया गया।

उन्हें 30 मई 2019 को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 30 जुलाई 2019 को भारत की संसद ने ट्रिपल तालक की प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा इसे 1 अगस्त 2019 से दंडनीय कार्य बना दिया। जिसे 19 सितंबर से लागू माना जाता है। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने राज्य सभा में अनुच्छेद 370 को भंग करने का संकल्प लिया और जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित किया।8 इस प्रकार अब जम्मू और कश्मीर एक केन्द्रीय शासित प्रदेश के रूप में कार्य करेगा तथा लद्दाख भी एक केन्द्रीय शासित प्रदेश होगा।

2019 में अयोध्या विवाद को हल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि देने का आदेश दिया।9

**स्वच्छता व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान**

प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले वर्ष में नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवा पर केंद्र सरकार द्वारा खर्च की गई राशि को कम कर दिया। मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में स्वास्थ्य के लिए नयी नीति प्रारंभ की। मोदी सरकार द्वारा स्वास्थ्य खर्चे में वृद्धि नहीं की गयी। निजी स्वास्थ्य संस्थानों को उन्होंने मजबूत किया। यह पिछली कांग्रेस सरकार की नीति से हटकर था। जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की सहायता के लिए कार्यक्रमों का समर्थन किया था। जिनमें बाल और मातृ मृत्यु दर को कम करना शामिल था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें इन सूचकांकों पर लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल थे, को पिछले वर्ष की तुलना में 2015 में लगभग 20% कम धनराशि प्राप्त हुई। तम्बाकू के उपयोग में कमी लाने एवं बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने पर जोर दिया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर ज्यादा ध्यान दी जाने की आलोचना की। 2018 में सरकार द्वारा स्वास्थ्य बजट 11.5ः./. बढ़ाया गया। इस बदलाव में सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लिए 2000 करोड़ का आवंटन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट में कमी शामिल थी। मेडिकल जर्नल लैंसेट के एक लेख में कहा गया है कि देश ष्मोदी मोदी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य में कुछ कदम पीछे ले गया हैष हो सकता है, 2018 में मोदी ने "आयुष्मान भारत योजना" शुरू की।10 एक सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका उद्देश्य 500 मिलियन लोगों का बीमा करना था। अक्टूबर 2018 तक 1,00,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।

मोदी ने अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में स्वच्छता पर अपनी सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। 2 अक्टूबर 2014 को, मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन ( स्वच्छ भारत ) शुरू किया(स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर 11 अभियान के घोषित लक्ष्यों में पाँच साल के भीतर खुले में शौच और मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करना शामिल था। कार्यक्रम के भाग के रूप में, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण शुरू किया और लोगों को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकार ने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना की भी घोषणा की। प्रशासन ने 2019 तक 60 मिलियन शौचालय बनाने की योजना बनाई। निर्माण परियोजनाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अक्टूबर 2014 में देश में स्वच्छता कवर 38.7ः./. से बढ़कर मई 2018 में 84.1./. हो गया। हालाँकि, नई स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग सरकार के लक्ष्यों से पीछे रह गया। 2018 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि स्वच्छता के प्रयास की शुरूआत के बाद भी ग्रामीण भारत 1,80,000 डायरिया से मौतें हुईं।

**प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की आर्थिक नीतियाँ**

नरेन्द्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। नरेन्द्र मोदी ने भारत की विदेशी निवेश नीतियों को लचीला बनाया।12जिसमें रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। अन्य प्रस्तावित सुधारों में श्रमिकों के लिए यूनियनों को तैयार करना और नियोक्ताओं के लिए उन्हें किराए पर लेना और उन्हें फायर करना, आसान बनाना शामिल था। इन प्रस्तावों में से कुछ को विरोध के बाद गिरा दिया गया था। सुधारों ने यूनियनों का कड़ा विरोध किया।

गरीबी घटाने के कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण उपायों के लिए समर्पित धन को मोदी प्रशासन द्वारा बहुत कम कर दिया गया था। सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च किए गए धन को कांग्रेस सरकार के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 14.6./. से घटकर मोदी के कार्यालय में प्रथम वर्ष के दौरान 12.6./. हो गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च में 15./. और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 16./. की गिरावट आई है। सर्व शिक्षा अभियान या सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन में 22./. की गिरावट आई है। सरकार ने व्यावसायिक करों में काफी कमी लाई एवं धन कर को समाप्त कर दिया। बिक्री करों में वृद्धि की तथा सोने और आभूषणों पर सीमा शुल्क कम कर दिया। नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2014 में अक्टूबर माह में डीजल के मूल्यों में कमी की।

नरेन्द्र मोदी ने भारत को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखकर सितम्बर 2014 में "मेक इन इंडिया" की शुरुआत की।[13] जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। उदारवादी आर्थिक विशेषज्ञों ने नरेन्द्र मोदी की इस पहल को अपना समर्थन दिया। आलोचकों ने यह कहा कि इससे विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजारों में हिस्सेदारी बढाने में मदद मिलेगी। मोदी के प्रशासन ने एक भूमि-सुधार विधेयक पारित किया, जिसने सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन किए बिना और इसके स्वामित्व वाले किसानों की सहमति के बिना निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दी। संसद में विरोध का सामना करने के बाद विधेयक को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पारित किया गया। मोदी सरकार ने आजादी के बाद से देश में सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विस

टैक्स (GST) को लागू किया। इसने 17 अलग-अलग करों को खत्म किया और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया।

अपने पहले कैबिनेट फैसले में मोदी ने काले धन की जांच के लिए एक टीम का गठन किया।[14] 9 नवंबर 2016 को सरकार ने भ्रष्टाचार, काले धन, जाली मुद्रा के उपयोग और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया। इस कदम से नगदी की भारी कमी हुई। भारतीय शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट आई और पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। आलोचकों ने कई मौतों का कारण ए.टी.एम. लाइन में लगना बताया। यह सब समाप्त हो जाने के बाद आयकर रिटर्न में हुई संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी और डिजिटल लेनदेन में बहुत वृद्धि देखी गयी।

मोदी के प्रीमियर के पहले चार वर्षों में भारत की जीडीपी 7.23./. की औसत दर से बढ़ी, जो पिछली सरकार के तहत 6.39./.की दर से अधिक थी।15 आय असमानता का स्तर बढ़ा। जबकि एक आंतरिक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2017 में, बेरोजगारी 45 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गई है। नौकरियों के नुकसान को 2016 के विमुद्रीकरण, और वास्तु और सेवा कर के प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

**प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश नीति**

विदेश नीति ने नरेन्द्र मोदी के चुनाव अभियान में अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाई। भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में विदेश नीति प्रमुखता से नहीं दिखाई गयी। नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के अन्य सभी नेताओं को आमंत्रित किया।16 वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे।

जनवरी 2018 में नई दिल्ली में मोदी ने म्यांमार की नेता आंग सान सू की से मुलाकात की। मोदी की विदेश नीति, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरह ही आर्थिक सम्बन्धों, सुरक्षा और क्षेत्रीय सम्बन्धों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। नरेन्द्र मोदी ने मनमोहन सिंह की बहु-गठबंधन की नीति को जारी रखा। मोदी प्रशासन ने मेक इन इंडिया जैसे नारों के साथ, विशेष रूप से पूर्वी एशिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया।[17] सरकार ने मध्य पूर्व में इस्लामिक राष्ट्रों जैसे बहरीन, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ-साथ इजराइल के साथ सम्बन्ध सुधारने का काफी प्रयत्न किया।

चुनाव के बाद पहले कुछ महीनों के दौरान नरेन्द्र मोदी ने अपनी नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई अलग-अलग देशों की यात्राऐं कीं और ब्रिक्स, आसियान और जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया।[18] नेपाल की यात्रा प्रधान मंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की पहली थी। जिसके दौरान उन्होंने नेपाल से एक बिलियन अमरीकी डालर की सहायता का वादा किया था। मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से भी अच्छे संबंध बनाए। जिसमें वहाँ के कई दौरे भी शामिल हैं। हालांकि, इसे एक अप्रत्याशित विकास के रूप में वर्णित किया गया था। क्योंकि अमेरिका ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मोदी को यात्रा वीजा से वंचित करने कर दिया था। जिस कारण दोनों देशों के बीच राजनैतिक और व्यापार सम्बन्धों को मजबूत करने की उम्मीद कम थी।

सन 2015 में भारतीय संसद ने बाँग्लादेश के साथ भारत-बांग्लादेश परिक्षेत्र के बारे में एक भूमि विनिमय सौदे की पुष्टि की। जिसे मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था। 1991 में स्थापित, भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी पर मोदी के प्रशासन ने नए सिरे से ध्यान दिया। इस नीति का नाम बदलकर षएक्ट ईस्ट पॉलिस रखा गया।[19] इसमें पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारतीय विदेश नीति को निर्देशित करना शामिल था। मणिपुर राज्य के माध्यम से म्यांमार के साथ भूमि संपर्क में सुधार के लिए सरकार ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसने म्यांमार के साथ भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव को विराम दिया। जिसने व्यापार पर सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

**भारत के प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की रक्षा नीति पर एक नजर**

नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले से हो रहे नाम मात्र सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि की नीति रखी। सैन्य बजट में मोदी के कार्यकाल में सकल घरेलू उत्पाद के एक अंश को देने की बात कही। सैन्य बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मियों की लागतों के लिए समर्पित गया। नरेन्द्र मोदी ने भारतीय सैन्य आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा बजट आरक्षित किया।

भाजपा के चुनाव घोषणापत्र ने पूर्वोत्तर में भारत में अवैध आव्रजन से निपटने का वादा किया गया था। साथ ही, विद्रोही समूहों से निपटने में भी अधिक दृढ़ता दिखाई। मोदी सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर भारत और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, और बौद्ध अवैध अप्रवासियों को भारत में अपने निवास को वैध बनाने की अनुमति दी। सरकार के इस कदम को मानवीय मूल्यों हेतु लिया जा रहा है। कई असमिया संगठनों की आलोचना भी की गयी।

नरेन्द्र मोदी प्रशासन ने "नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड" NSCM(के सबसे बड़े गुट के साथ एक शांति समझौते पर बातचीत की जिसकी घोषणा अगस्त 2015 में की गई। पूर्वोत्तर भारत में नागा विद्रोह 1950 के दशक में शुरू हुआ था। एनएससीएम और सरकार ने 1997 में संघर्ष विराम के लिए सहमति व्यक्त की थी। परन्तु, पहले शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में NSCMके खापलांग गुट के साथ 15 साल के युद्धविराम की बात को रद्द कर दिया।NSCM-K विभिन्न हमलों का जवाब दिया। जिसमें 18 लोग मारे गए। मोदी सरकार ने परिणाम स्वरूप म्यांमार के साथ सीमा पर छापा मारा और NSCM-K को आतंकवादी संगठन करार दिया।

मोदी ने अपने चुनाव अभियान के दौरान पाकिस्तान पर सख्त होने का वादा करते हुए बार-बार कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यातक है। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने कहा कि उसने आजाद कश्मीर में आतंकी लॉन्चपैड पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था विवेचनारू कितना कठिन था "सर्जिकल स्ट्राइक" करके जिंदा लौटना?।20 भारतीय मीडिया ने दावा किया कि हड़ताल में 50 आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने तो शुरू में इनकार कर दिया कि कोई भी हमला हुआ है बाद की रिपोर्टों ने बताया कि हताहतों की संख्या के बारे में भारतीय दावा सही था। हालाँकि सीमा पार से हमले किए गए थे। फरवरी 2019 में भारत ने एक कथित आतंकवादी शिविर के खिलाफ पाकिस्तान में हवाई हमले किए। सीमा पार से गोलाबारी और एक भारतीय विमान के नुकसान सहित आगे की सैन्य झड़पें हुईं।

**अध्ययन का उद्देश्य**

1. नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने तक की राजनीतिक पृष्ठभूमि को ज्ञात करना।
2. नरेंद्र मोदी की राजनीति एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच अंतर संबंधों को ज्ञात करना।
3. मोदी के व्यक्तित्व एवं सरकारी नीतियों का विश्लेषण करना।
4. भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों एवं असफलताओं का मूल्यांकन करना।

**शोध प्रविधि**

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्यों को संकलित किया गया है। इसके अंतर्गत अनुसंधानों, सर्वेक्षणों, पुस्तकों, विभिन्न जनरल, समाचार पत्र,पत्रिकाओं, गजेटियर, रिपोर्टो, सरकारी दस्तावेजों, केंद्र सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़े एवं प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित और वर्गीकृत कर इनका विश्लेषण किया गया है और विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किया गया है।

**साहित्यावलोकन**

1. रेनू सैनी (2018) मोदी सक्सेस गाथा में बताया कि मोदी के बचपन से लेकर जीवन में जितनी भी प्रगति हुई उनको कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी ने अपनी योग्यता और कुशलता एवं अपने नीतियों कार्य क्षमता से अधिक सक्षम वर्ग पर प्रभाव डाला तो आम जनता ने उनको अपना सर्वोपरि प्रधानमंत्री माना है। आज के समय में प्रत्येक वर्ग समाज का एक साधारण व्यक्ति भी अपनी बात नरेंद्र मोदी तक आसानी से पहुंचा सकता है साथ ही उनसे मिल भी सकता है।
2. वीरेंद्र सिंह (2015) ष्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान में बताया कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 योजनाओं की घोषणा की पहली स्वच्छ भारत मिशन, दूसरी राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन एक प्रधानमंत्री जन धन योजना इन घोषणाओं को लागू करने का उद्देश्य था कि देश का हर वर्ग के नागरिक इसमें सहभागिता देगा। जिससे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी का विकास संभव होगा।
3. संतोष कुमार (2015) भारत कैसे हुआ मोदी मय में लेखक ने बताया कि भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव के कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। आने वाले प्रत्येक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते रहे जिससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बताया जो अपनी राजनीतियों के दम पर ही 2019 में विजय मार्ग का रास्ता निकाल लिया। इसी जीत ने सभी सामान्य जनता के मन में यह बात विचार में ला दी कि ऐसा कैसे संभव है बहुत ही लंबे समय से भाजपा की छवि बनी हुई थी कि यह पार्टी ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण की ही पार्टी है, जिसको इस बार पूरी तरह से तोड़ दिया गया।
4. झा प्रशांत (2017)कैसे जीतती है भाजपा में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव कैसे जीत जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्या कर लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कोई नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ऐसी क्या रणनीति है कि, वह चुनाव के समय मदद करता है, जिससे पार्टी को जीत मिल जाती है यदि अमित शाह का चुनाव प्रबंधन और उनकी चुनावी गणित इतनी सक्रिय है तो बिहार विधानसभा चुनाव में उनका कौशल क्यों असफल हो गया।
5. सिंह बीरेंद्र (2017) "नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत" में बताया गया की यह एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की कहानी है जो भारत का प्रधानमंत्री तो बना, लेकिन राजनीति शुरुआत के दौर में विरोधियों ने जितना विरोध किया उनके समर्थकों ने उनको उतना ही समर्थन किया। 16 वीं

लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने कांग्रेस के विरोध की और भाजपा के प्रति विश्वास और समर्थन को महसूस किया। मोदी के ऊपर एक आरोप लगता था कि, वो तानाशाह की तरह काम करते हैं लेकिन उन्होंने इस बात को झूठा साबित करने के लिए चुनाव प्रचार अभियान में एक संयुक्त डोली की तरह काम किया। साथ ही जनता को विश्वास दिलाया कि दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं।

**निष्कर्ष**

भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं मजबूत लोकतांत्रिक देश ह क्योंकि यहां जनता का ,जनता द्वारा, जनता के लिए शासन की व्यवस्था की गई है। जनता के प्रतिनिधि के रुप में प्रधानमंत्री की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसी संदर्भ में नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को लिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी के उपरोक्त कार्यो कायदि हम विश्लेषण करें तो हम यह पाते हैं कि नरेंद्र मोदी की नीतियां यथार्थवादी एवं अभिनव रही हैं। इस बात की पुष्टि उनके प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद हो गई थी जब उन्होंने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित किया जिसका सीधा मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की पहली वरीयता यह पड़ोसी देश है। मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक दोस्त का विकल्प हो सकता है परंतु पड़ोसियों का नहीं। मोदी द्वारा अपनाई गई इन अभिनव नीतियों के पीछे उनका पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना भी रहा है क्योंकि उन्हें संसद में विधेयक पास कराने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा अतः वह एक सशक्त प्रधानमंत्री की छवि के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. *https://pmmodiyojana.in/pradhanmantri-kaushal-vikas-yojana/*
2. *https://www.pmindia.gov.in/hi/*
3. *http://loksabhahindiph.nic.in/CommonParliament.aspx?fmane=par1.htm*
4. *https://www.pmindia.gov.in/hi/*
5. *https://caravanmagazine.in/reportage/emperor-uncrowned-narendra-modi-profile-hindi*
6. *https://www.bbc.com/hindi/india-48384680*
7. *https://www.bbc.com/hindi/india/2014/05/140516_narendra_modi_varansi_win_rns*
8. *https://www.niti.gov.in/niti/hi/content/niti-aayog-one-year*
9. *https://www.bbc.com/hindi/resources/idt-ffb901e8-5bc7-498c-8bd5-94b4fa95929a*
10. *http://loksabhaph.nic.in/Debates/Result17.aspx?dbsl=776&ser=&smode=t*
11. *https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates*
12. *https://www.india.gov.in/hi/spotlight*
13. *http://yojana.gov.in/Yojana-January 2018-final.pdf*
14. *http://yojana.gov.in/HindiYojanaApril2015.compressed.pdf*
15. *https://loksabha.nic.in/Members/DebateResults16.aspx?mpno=13266*
16. *https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/vol2chapter/hechap01_vol2.pdf*
17. *https://mea.gov.in/distinguished-lectures-detail-hi.htm?859*
18. *https://www.india.gov.in/hi/spotlight*
19. *https://mea.gov.in/in-focus-article-hi.htm?19954/G20+Mexico+Summit*
20. *https://mea.gov.in/in-focus-article-hi.htm?24216/Act+East+Indias+ASEAN+Journey*
21. *https://www.bbc.com/hindi/india-41362477*